



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1—सितम्बर 7, 2007 (भाद्रपद 10, 1929)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1—SEPTEMBER 7, 2007 (BHADRA 10, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	891	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	865	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4043
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1323	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	603
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	10709
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	615
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*		

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	891	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	865	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1323	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4043
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	603
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	10709
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	615
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2007

संकल्प

सं. I/20017/01/2004-रा.भा. (नीति-1)--भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसे दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के संकल्प संख्या I/20017/01/2004-रा.भा. (नीति-1) द्वारा अधिसूचित किया गया था, का कार्यकाल एक वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 15.12.2007 से 14.12.2008 तक बढ़ाया जाता है।

पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी
संयुक्त सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2007

सं. 2/13/2006-आई सी--भारत के राष्ट्रपति, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से "उत्तर पूर्वी राज्य सड़क परियोजना (एन ई एस आर पी)" के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति/परियोजना समन्वयन समिति का गठन करते हैं। समिति का गठन तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक निम्नलिखित संघटन के अनुसार होगा :--

- | | |
|------------------------------------------------------|---------|
| 1. सचिव, डोनर | अध्यक्ष |
| 2. सचिव, एन ई सी सचिवालय, शिलांग | सदस्य |
| 3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (गृह एवं डोनर) | सदस्य |
| 4. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) | सदस्य |
| 5. प्रधान सलाहकार (परिवहन), योजना आयोग | सदस्य |
| 6. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) | सदस्य |
| 7. संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय | सदस्य |
| 8. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | सदस्य |
| 9. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय | सदस्य |
| 10. संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | सदस्य |

- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| 11. संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय | सदस्य |
| 12. संयुक्त सचिव (एच के) डोनर मंत्रालय | सदस्य |
| 13. निदेशक (आई सी) डोनर मंत्रालय | सदस्य सचिव |
| 14. डोनर मंत्रालय द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य | |
| | सी बिस्वास
अवर सचिव |

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. एफ. 9-37/2006-यू-3 (ए)--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत गांधी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश, जिसके अंतर्गत 6 संस्थाएं चलाई जा रही हैं को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 17 जुलाई, 2007 के अपने पत्र संख्या एफ 6-23/96 (सी.पी.पी.-1) सिफारिश की है कि उक्त संस्थाओं को गांधी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश के नाम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम-विश्वविद्यालय घोषित किया जाए;

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा गांधी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश जिसमें केवल इसके (1) कालेज आफ इंजीनियरी (2) कालेज आफ साइंस शामिल हैं, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। इसे सम-विश्वविद्यालय का दर्जा उस तारीख से दिया जाएगा जिस तारीख से इसका अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय नामतः आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश से सम्बद्धन समाप्त हो जाता है।

5. उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

6. भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गांधी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, या इसकी संघटक शिक्षण इकाईयों को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 17 अगस्त 2007

सं. एफ. 9-28/2001-यू.-3--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पेरियार मनियम्माई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 17 जुलाई, 2007 के अपने पत्र संख्या एफ 6/75/2004 (सी.पी.पी.-1) सिफारिश की है कि पेरियार मनियम्माई विज्ञान

और प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम-विश्वविद्यालय घोषित किया जाए;

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा पेरियार मनियम्माई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु जिसमें पेरियार मनियम्माई महिला प्रौद्योगिकी कालेज, तंजावुर शामिल हैं, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। इसे सम-विश्वविद्यालय का दर्जा उस तारीख से दिया जाएगा जिस तारीख से इसका अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय नामतः अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु से सम्बद्धन समाप्त हो जाता है।

5. उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

6. भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पेरियार मनियम्माई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी संघटक शिक्षण इकाईयों को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 22nd August 2007

RESOLUTION

No. I/20017/01/2004-O.L.(Policy-1).—The Government of India extends the term of the Kendriya Hindi Samiti, notified vide Resolution No. I/20017/01/2004-O.L.(Policy-1) dated 15.12.2004, for one year i.e. from dated 15.12.2007 to 14.12.2008.

P. V. VALSALA G. KUTTY
Jt. Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN
REGION

New Delhi, the 9th August 2007

No. 2/13/2006-IC.—The President of India is pleased to constitute the National Level Steering Committee/Project Coordination Committee for implementation of 'North Eastern State Roads Project (NESRP)' assisted by the Asian Development Bank. The Committee is constituted with immediate effect and until further orders with the following composition :—

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Secretary, DONER | Chairperson |
| 2. Secretary, NEC Sectt. Shillong | Member |
| 3. Additional Secretary & Financial Adviser (Home & DONER) | Member |
| 4. Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure) | Member |
| 5. Principal Adviser (Transport), Planning Commission | Member |
| 6. Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) | Member |
| 7. Joint Secretary, Ministry of Road Transport and Highways | Member |
| 8. Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests | Member |
| 9. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs | Member |
| 10. Joint Secretary, Ministry of Urban Development | Member |
| 11. Joint Secretary, Ministry of External Affairs | Member |
| 12. Joint Secretary (HK) MDONER | Member |
| 13. Director (IC) MDONER | Member Secretary |
| 14. Any other Member as nominated by the MDONER | |

C. BISWAS
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 13th August 2007

No. F. 9-37/2006-U.3(A).—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, a proposal was received for grant of status of deemed-to-be-university to Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam, Andhra Pradesh, comprising six institutions run by it, under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, the University Grants Commission have examined the said proposal and vide their communication No. F. 6-23/96(CPP-I) dated the 17 July, 2007 have recommended conferment of status of 'deemed-to-be-university' to Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam, Andhra Pradesh, under Section 3 of the UGC Act, 1956.

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that 'Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam, Andhra Pradesh, comprising its (i) College of Engineering and (ii) College of Science only, shall be deemed to be a university for the purposes of the aforesaid Act, with effect from the date on which the College of Engineering and the College of Science are disaffiliated from their affiliating university, viz., Andhra University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

5. The declaration made in para 4 above is also subject to further conditions mentioned at Sr. No. 4 of the endorsement to this Notification.

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to GITAM or its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

The 17th August 2007

No. F. 9-28/2001-U.3.—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, a proposal was received for grant of status of deemed-to-be-university to Periyar Maniammai Institute of Science & Technology (PMIST), Thanjavur, Tamil Nadu, under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, the University Grants Commission have examined the said proposal and vide their communication No. F. 6-75/2004(CPP-I) dated the 17 July, 2007 have recommended conferment of status of 'deemed-to-be-university' to Periyar Maniammai Institute of Science & Technology (PMIST), Thanjavur, Tamil Nadu, under Section 3 of the UGC Act, 1956.

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that 'Periyar Maniammai Institute of Science & Technology (PMIST), Thanjavur, Tamil Nadu, comprising of Periyar Maniammai College of Technology for Women, Thanjavur, shall be

deemed to be a university for the purposes of the aforesaid Act, with effect from the date on which the College of Engineering and the College of Science are disaffiliated from their affiliating university, viz., Anna University, Chennai, Tamil Nadu.

5. The declaration made in para 4 above is also subject to further conditions mentioned at Sr. No. 4 of the endorsement to this Notification.

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to PMIST or its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.